(b) if so, what is the result thereof; and

(c) what is the quantum of resources being mobilised for Kayamkulam Combined Cycle Project and various other power projects thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI MATI. URMILABEN CHIMANBHAI PATIL): (a) and (b) Yes, Sir. A delegation, comprising of representatives from National Thermal Power Corporation (NTPC) and Ministry of Power, visited World Bank, Washington, D.C. in the 2nd week of May 1995, primarily to settle the issue of bid documents for the Kayamakulam Combined Cycle Power Project. During the discussions, various issues connected with the bid documents have been resolved. An understanding has also been reached with the World Bank for issuing of the bid documents. The tender for the main plant equipment is being issued with an indication that World Bank funding is likely to be available for this project.

(c) The estimated cost of the project is Rs. 1310.58 crores, based on 3rd quarter, 1994 price level. The World Bank has already provided a loan of US dollar 400 million for funding NTPC's investment programmes for new projects, subject to their meeting the eligibility criteria laid down in the loan agreement. Vindhyachal Super Thermal Power Project Stage-II is presently being implemented by NTPC under the time-slice loan of the World Bank.

उत्तरी भारत में विद्युत संकट

7887. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 मई, 1995 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "पावर क्राइसेस लाइकली टु हिट नार्थ इंडिया सीवियरली" शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि आठवां पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक देश के उत्तरी राज्यों में विशेषकर पंजाब, हरियाणा राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली इत्यादि में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर 50 प्रतिशत तक होने का संभावना हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इस अंतर को पाटने के लिये कोई उपाय किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल) : 1995–96 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के प्रत्याशित विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)	
चण्डीगढ़	775	775	—	—
दिल्ली	13500	12983	—597	(4.4)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी	(%)
हरियाणा . . .	13100	11383	−1717	(13.1)
हिमाचल प्रदेश . .	1950	2479	+529	(27.1)
जम्मू व कश्मीर . .	4300	3445	−855	(19.1)
पंजाब . . .	21000	20050	−950	(4.5)
राजस्थान . . .	18300	16195	−2105	(11.5)
उत्तर प्रदेश . . .	39500	37089	−2411	(6.1)
उत्तरी क्षेत्र . . .	112425	104319	−8106	(7.2)

(ख) और (ग) देश में 20729.7 मे.वा. की संभावित क्षमता अभिवृद्धि के आधार पर आठवीं योजना के अंत में अर्थात् 1996-97 में उत्तरी क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली आदि राज्यों में विद्युत आपूर्ति की प्रत्याशित स्थिति निम्नलिखित है :-

	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
व्यस्ततम कालीन मांग (मेगावाट) .	24234	4482	3058	3851	8253	2532
व्यस्ततम कालीन उपलब्धता (मेगावाट)	14896	2853	1530	1942	5150	1745
कमी . .	9338	1629	1528	1909	3113	787
(%) प्रतिशत .	38.5	36.3	50.0	49.6	37.7	31.1
ऊर्जा आवश्यकता (मि०यू०) .	129587	23851	15183	22232	43597	14416
ऊर्जा उपलब्धता (मि०यू०) .	105401	20335	10148	12572	37852	13153
कमी . .	24186	3517	5035	9660	6105	1263
(%) प्रतिशत .	18.7	14.7	33.2	43.5	13.9	8.8

(घ) और (ङ) मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने हेतु उत्पादन को अधिकतम करने, विद्युत में कटौती लागू करने, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने, मांग पक्ष प्रबंधन करने आदि का आश्रय लिया गया है ।

किए जा रहे विभिन्न उपायों में नई उत्पादन क्षमता को शीघ्रता से चालू करना, अल्पकालीन निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग प्रबंध

और ऊर्जा संवर्धन उपायों का क्रियान्वयन करना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कम ऊर्जा वाल क्षत्रों में ऊर्जा का अंतरण करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देना शामिल है ।

Private Power Projects

7888. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of power projects set up/to be set up State-wise under the private sector with or without foreign collaboration and clearance given by his Ministry and FIPB so far;

(b) the names and details of foreign and Indian participants with the amount of investments proposed, time-schedule of completion of each such project;

(c) whether it is a fact that foreign investment in any form has not been transferred to Indian soil till now;

(d) whether such projects are mostly proposed to be run with the shareholders money to be obtained from Indian public;

(e) whether the foreign participants are more keen for their sale of entire projects though some of the items are widely available in Indian markets;

(f) if so, the facts and details thereof; and

(g) what steps are being contemplated for ensuring actual investments from foreign participants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATIL): (a) and (b) The details of the power projects proposed to be set up in the private sector are given in the Annexure. (*See* Appendix 173, Annexure No. 177). The details of projects recommended by Foreign Investment Promotion Board (FIPB) and cleared by Cabinet Committee on Foreign Investment are given in the enclosed Statement. (*See* below). The time schedule of completion of each project could be indicated only after these projects achieve financial closure. So far only one project viz., Dabhol Power Project of Maharashtra has achieved financial closure and is scheduled for completion by June, 1998.

(c) to (e) No, Sir.

(f) to (g) Do not arise.

Statement

List of CCFI cleared private power projects

S.No.	Name of the project/State	Promoter	Cap. (MW)	Prov. Cost (Rs Crs)
1	2	3	4	5
1	Godavari GBPP/AP	Spectrum Tech, USA	208	748.43
2	Jegurupadu GBPP/AP	GVK,USA	235	827.00
3	Dabhol TPS/MAH	Enron/Bechtel/ GE,USA	2015	9052.00
4	*Zero* Unit NLC/TN	ST Power/CMS Gen ,USA	250	125.11